Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 अंक 12 रविवार, फरीदाबाद, 16-31 मई, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

नगर निगम चुनाव लेकिन नगर उदासीन

फरीदाबाद (म.मो.) नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होने में अब मुश्किल से चार दिन और रह गये हैं। इस बीच सभी वार्डों से भांति-भांति के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। लगभग एक माह तक चले चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों ने लोगों को तरह-तरह से अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया और तरह-तरह के करतब दिखाये। सबों ने एक स्वर से कहा कि वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी करेंगे और अपने वार्ड को स्वर्ग जैसा बना देंगे। पार्षद बनने पर वे लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि वे किसी भी समस्या का समाधान चौबीस घंटों के भीतर करायेंगे। कुछ ने कहा कि समस्याओं का समाधान कराने के लिए यदि उन्हें मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिलना पड़े तो वे मिलेंगे और समस्या का समाधान नहीं किये जाने पर उनकी कोठी के समने आत्मदाह तक कर लेंगे। प्रचार के इस स्तर और शैली पर समझदार लोग हंसते रहे और मजे लेते रहे। वहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके छलावे में आये अथवा जिनके हित इनके साथ जुड़े रहे, उन्होंने इनके पीछे-पीछे चलना ही ठीक समझा।

इस चुनाव में उतरे ऐसे उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है जो पहले भी पार्षद रहे हैं और जिनके कार्यों को जनता ने भलीभांति देखा है। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पहली बार चुनाव के इस समर में उतरे हैं और जिन्हें देखना जनता को अभी बाकी है। जो लोग पार्षद रह चुके हैं, उनसे जनता के सामने यह पूछने का अवसर है कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने उसकी समस्याओं के हल के लिए क्या किया?

- शेष पेज 2 पर

लाखों-करोड़ों खर्च कर के पार्षद बनना क्यों चाहते हैं?

'जनसेवा' का इतना जुनून कि लाखों बल्कि कुछ मामलों में तो करोड़ों तक खर्च कर के दिन-रात एक किये हुए हैं। दिन-रात वातानुकूलित रहने वाले दिन की भरी दुपहर में सड़क-दर-सड़क, गली-दर-गली, हर घर भिखारियों की तरह वोट मांग रहे हैं। जहां मांगने से वोट न मिल रहा हो, वहां तरह-तरह के दबाव व धन का इस्तेमाल करने में भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जहां कोई व्यक्ति खुद (आरक्षण के कारण) चुनाव लड़ने में असमर्थ होता है, वहां वह अपने घर की किसी भी महिला को चुनाव लड़ा कर चौधर अपने ही घर में रखना चाहता है। आखिर यह सब क्यों? क्या यह सब वास्तव में ही जनता की सेवा के लिए किया जा रहा है? नहीं, कतई नहीं। पल्ले से भारी भरकम खर्च व इतनी सख्त मेहनत जनता की सेवा के लिए करने वाला कोई सूरमा नज़र नहीं आता। गत पंद्रह सालों से निगम पार्षदों का हालचाल एवं बही-खाते की जानकारी रखने वाले सभी लोग भली भांति जानते हैं एकाध अपवाद स्वरूप को छोड़ कर शेष सभी पार्षदों ने इसे एक राजनीतिक व्यवसाय का दर्जा दे कर रखा है जिसके द्वारा चुनाव में खर्च किये गये धन से कई गुणा अधिक बटोरने का प्रयास किया गया है। वास्तव में अधिकांश पार्षदों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि पार्षद के क्या कर्त्तव्य तथा क्या अधिकार हैं तथा वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इन्हें यदि इस बात का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो सैंकड़ों करोड़ का निगम बजट मात्र पांच मिनट में ही पास न हो गया होता।

- शेष पेज 2 पर

भ्रष्टाचार मिटाने के सरकारी दावे खोखले

डॉक्टर से बने थानेदार की डकैतियां जारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) 16-30 अप्रैल के अंक में डॉक्टर से थानेदार बने सुनील के कुछ कारनामों का उल्लेख किया गया था ताकि भ्रष्टाचार मिटाने एवं स्वच्छ प्रशासन देने का ढोल पीटने वाली सरकार एवं इसके वरिष्ठ अधिकारी उस पर कुछ अंकुश लगा सके। लेकिन उसके द्वारा निरंतर जारी लूट एवं डकैती अभियान से सिद्ध होता है कि उसके द्वारा की जा रही लूट के पीछे सरकार एवं इसके उच्च अधिकारियों का भी पूरा समर्थन है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस थानेदार की बल्लबगढ़ स्थित सीआईए चौकी में ख़बर लिखे जाने के वक्त यानी 15.5.10 को भी एक ट्रक नं.एच आर-18 पी-2344 जो 32 फुट लंबा है, खड़ा है जो 8.5.10 को इसने कब्ज़े में लिया था। सप्ताह भर से खड़े इस ट्रक तथा इसके साथ पकड़े गये दो लोग़ों का पुलिस रिकार्ड में कहीं कोई इन्द्राज नहीं है यानी कि न तो ट्रक को कब्ज़े में लिया दिखाया गया है और ना ही किसी की गिरफ़्तारी डाली गई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ट्रक दक्षिण भारत (कोयम्बटूर) से जनाना अधोवस्त्र भर कर दिल्ली के लिए चला था। आगरा के आस-पास इसके ड्राइवर तथा क्लीनर ने इसे बेच दिया तथा थाने में जा कर बताया कि कोई चार बदमाश हथियारों के बल पर उनसे ट्रक लूट कर ले गये। लेकिन यूपी पुलिस की पूछताछ में शीघ्र ही सच्चाई सामने आ गई। इधर यह ट्रक जब हरियाणा की सीमा से गुजर रहा था तो थानेदार सुनील के हाथ लग गया और ला कर चौकी में खड़ा कर लिया। सुनील ने करीब आधा ट्रक माल खुर्द बुर्द कर दिया तथा पकड़े हुए चारों लोग़ों को इतना पीट दिया कि वे कहीं पेश किये जाने की हालत में नहीं हैं। उधर यूपी पुलिस भी सूंघते-सूंघते ट्रक तक पहुंच गई। अब समस्या यह खड़ी हो गई कि आधे ट्रक व अधमरे लोग़ों को यूपी पुलिस कैसे कब्ज़े में ले ले।

गौर से देखा जाये तो यह मामला लूट अथवा डकैती का तो बनता नहीं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर व क्लीनर ने अपनी मर्ज़ी से भरा हुआ ट्रक इन्हें बेचा था और वह भी यूपी में। सुनील द्वारा इन्हें पीटे जाने के पीछे उद्देश्य केवल एक ही था, मोटी रिश्वत और वह भी तुरंत। तुरंत दे पाने में वे असमर्थ थे, लिहाज़ा सप्ताह भर तक पिटते रहे। ख़बर लिखते-लिखते पता चला है कि 14 की रात में दोनों की गिरफ़्तारी आईपीसी की धारा 398, 401 में डाल दी है। मजे की बात यह है कि इस बार किसी भी मातहत ने पर्चा देने से मना कर दिया तो इसे खुद ही मुकदमा दर्ज करना पड़ा। यहां अब एक और क्लेश पैदा हो गया कि यूपी पुलिस ने तो ड्राइवर-क्लीनर के खिलाफ अमानत में खयानत का पर्चा दज किया है और यहां चोरी का माल खरीदने वालों के विरुद्ध डकैती का।

- शेष पेज 2 पर

ईएसआई में श्रमिकों की दुर्दशा : श्रममंत्री अपने धंधों में मस्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) श्रमिकों के वेतन से काटे गये पैसे से केंद्र सरकार द्वारा ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) नामक एक संगठन चलाया जाता है। इस संगठन द्वारा श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए पूरे देश भर की तरह हरियाणा में भी हस्पताल व डिस्पेंसरियां खोली गई हैं, जिनके द्वारा बीमाकृत श्रमिकों व उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

देश के संविधान के अनुसार स्वास्थ्य सेवायें क्योंकि राज्य की सूची में भी आती हैं, इसलिए राज्य भर में ईएसआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के कुल खर्च का 1/8 भाग राज्य सरकार को देना होता है। इस हिसाब से यदि राज्य भर में ईएसआईसी की स्वास्थ्य सेवाओं पर 144 करोड़ रुपये का खर्च आये तो राज्य सरकार को मात्र 18 करोड़ रुपये अपने हिस्से के तौर पर देने पड़ेंगे। लेकिन मूर्खों तथा श्रमिकों के दुश्मनों द्वारा चलाई जा रही हरियाणा की सरकार ने वर्ष 2010-11 का यह बजट मात्र 82 करोड़ का बनाया है जिस पर सरकार को मात्र 10.25 करोड़ रुपये अपने हिस्से के तौर पर देने पड़ेंगे। जबकि वर्ष 2009-10 में यह बजट 77 करोड़ रुपये का बना था जिस पर राज्य सरकार को 9 करोड़ की जगह 11 करोड़ रुपये अपने हिस्से के तौर पर देने पड़े थे। यहां 1.4 करोड़ फालतू इसलिए देने पड़े थे, क्योंकि इसमें वेतन भाग अधिक था। इस बार इन मूर्ख लोगों ने अपनी अक्ल का कुछ अधिक इस्तेमाल करते हुए वेतन भाग को कम करके बजट को 57 करोड़ की जगह 51 करोड़ का बना दिया। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वेतन भाग कम कैसे हुआ? राज्य भर के ईएसआई हस्पतालों व डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों के कुल स्वीकृत पद गत बीसियों बरस से 293 हैं। वर्ष 2003-04 में जब बीमाकृत श्रमिकों की संख्या 4,31000 थी, तब भी डॉक्टर इतने ही थे और आज इनकी संख्या 8,40000 हो गयी है जो अगले वर्ष यानी 31.3.11 तक बढ़ कर 10 लाख हो जायेगी, तो भी डॉक्टरों की संख्या उतनी ही बनी रहेगी। डॉक्टरों की वास्तविक संख्या इतनी भी बनी रहती तो भी शायद कुछ राहत होती, लेकिन वास्तविक संख्या तो घट-घट कर 180 रह गई है तथा अगले दस माह में और भी घट कर 150 रह जायेगी। ऐसा इसलिये हो रहा है कि जो डॉक्टर सेवानिवृत या अन्यथा नौकरी छोड़ कर जाते हैं उनकी जगह नये डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जाती, क्योंकि भर्ती करने से बजट बढ़ जाता है जिसे राज्य सरकार बढ़ाना नहीं चाहती। संदर्भवश यहां पर यह समझ लेना भी जरूरी है कि डॉक्टरों की संख्या के साथ-साथ अन्य स्टॉफ तो इससे भी तीव्र गति से घट रहा है। ईएसआईसी मानकों के अनुसार राज्य भर में डॉक्टरों की संख्या 600 तथा इसी अनुपात में अन्य सहायक स्टॉफ़ भी होना चाहिए। लेकिन जनहित की लंबी-चौड़ी नौटंकियां करने वाली हरियाणा सरकार को जनहित से क्या लेना-देना, उसे तो लूटने-खाने से फुर्सत मिले तो वह जनहित देखेगी ना। ईएसआई के लिए वेतन सीमा 10,000 से बढ़ कर 15000 हो जाने से इस वर्ष में बीमाकृत श्रमिकों की संख्या में कम से कम एक लाख की और अतिरिक्त वृद्धि होना तो तय है। इसके बाद जो ईएसआई में श्रमिकों की दुर्गति होगी, वह और भी भयंकर होगी। इसी दुर्गति से बचने के लिए जहां तक संभव हो सकता है, श्रमिक ईएसआई जाने से बचता है। वह 100-50 रुपये अपनी बस्ती के नीम-हकीम को दे कर इलाज कराना बेहतर समझता है।

- शेष पेज 2 पर

सरकार की मूर्खता का एक और नमूना

ईएसआई हस्पतालों के लिए साजो-सामान खरीदने के लिए 23.3.10 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में हुई। इसमें फरीदाबाद के दो अस्पतालों के लिए 20-20 लाख की दो मशीनें (होल बॉडी कलर्ड डोप्लर - जो कि एक प्रकार की उन्नत अल्ट्रा साऊंड मशीन होती है) खरीदने की बात आई तो मुख्यमंत्री ने अपने ही जैसे मूर्ख डॉक्टर नरवीर सिंह, जो कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख हैं, से पूछा कि भई यह क्या होता है और क्यों खरीदना है? नरवीर सिंह ने कहा कि जी अपने (राज्य के) तो किसी हस्पताल में ऐसी कोई मशीन है नहीं। इस पर मुख्यमंत्री ने झट से कहा तो फ़िर ईएसआई में इसकी क्या जरूरत है? छोड़ो परे। बस इसके बाद डिजिटल एक्स-रे व अन्य मशीनों की बात चलाने की किसी की हिम्मत न हुई। इसके चलते ईएसआई कारपोरेशन से मिलने वाला एक करोड़, 28 लाख रुपया 31.3.10 को लैप्स हो गया। जैसा कि लिखा जा चुका है कि राज्य सरकार को तो बजट का मात्र आठवां भाग ही देना पड़ता है, यानी कि 40 लाख के दो होल बॉडी डोपलर खरीदने पर राज्य सरकार को मात्र पांच लाख ही तो खर्च करने थे। यदि राज्य सरकार के अपने किसी हस्पताल में यह मशीन नहीं है तो क्या ईएसआई हस्पतालों में ऐसी मशीन लाना गुनाह है? यह निरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? मनुष्यों के लिए बेशक डिजिटल एक्स-रे न हो, लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के पशु चिकित्सालय में पशुओं के लिए जरूर इसे उपलब्ध कराया गया है, जहां दिन भर में चार-पांच पशुओं का ही एक्स-रे होता है। यानी कि इस व्यवस्था एवं कुशासन में श्रमिक पशुओं से भी बदतर हो गये हैं।